स्वच्छ भारत
सम्पूर्ण स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छता समाचार

जून 2024

विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून, 2024

स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण

@swachhbharat @SBMGramin @SwachhBharatMissionGramin @swachh_bharat @swachhbharatgrameen

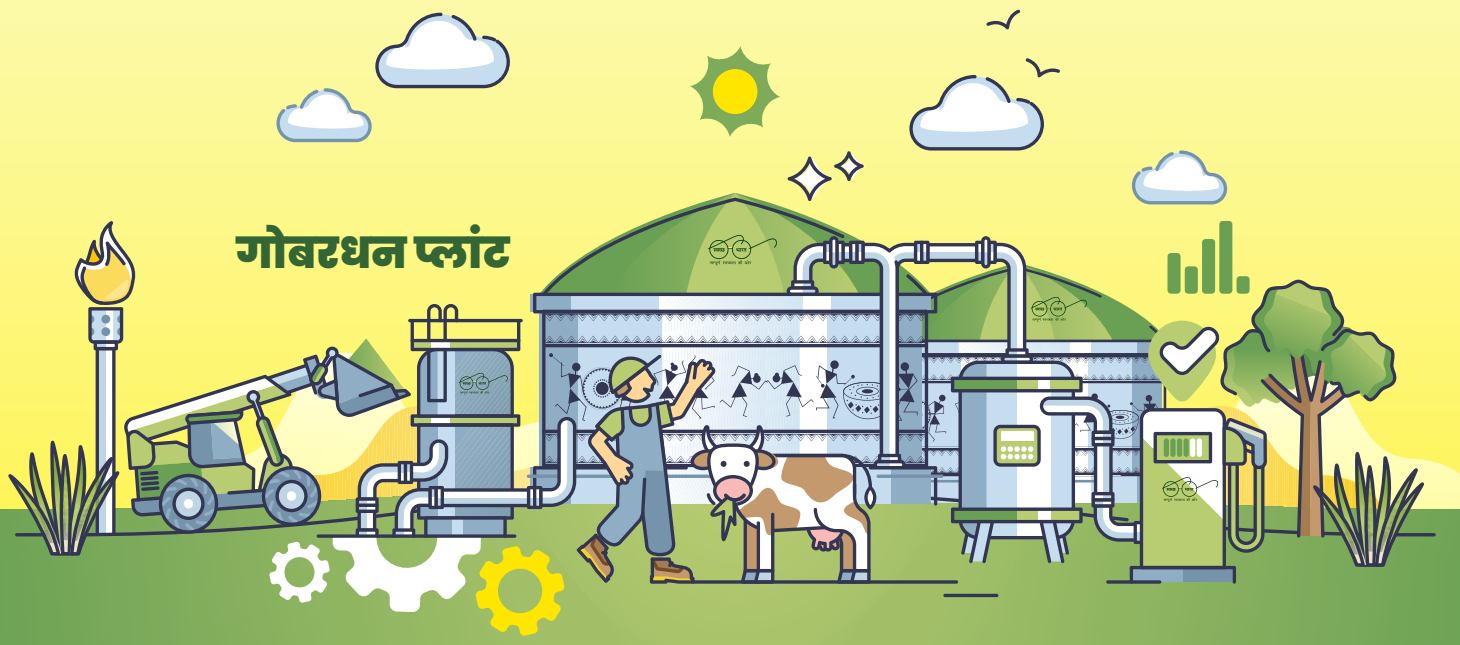

स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियाँ (मई, 2024)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

- टीम द्वारा कार्यालय परिसर में कूड़ा फैलाने और थूकने वाले उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज के माध्यम से वृहद स्तर पर कार्रवाई की गई।
- श्रम शक्ति भवन के गलियारे/शौचालय और भंडारण स्थानों सहित कार्यालय परिसर की सफाई की गई और फ्लोर प्रभारी द्वारा निरीक्षण किया गया।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वच्छता शपथ समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव, श्रम एवं रोजगार ने की।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- स्वच्छता अभियान का उद्घाटन शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से पखवाड़ा मनाया गया। मंत्रालय ने गहन सफाई अभियान चलाया, जिससे अप्रचलित और अनुपयोगी मरम्मत वस्तुओं का निपटान सुनिश्चित हुआ। उन्होंने 11 मई को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उत्सव भी मनाया।
- इस माह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) में अंतर-विभागीय और अंतर-अनुभागीय स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- टीम ने कार्यालय परिसर से कचरा हटाना भी सुनिश्चित किया तथा परिसर के बाहर फुटपाथ क्षेत्र की सफाई भी कराई, जिसमें PWD रोड से सटा क्षेत्र भी शामिल था।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

- सभी कमरों में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखने के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखे गए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाई गई, जिसके बाद कमरों और सभी कार्यालय परिसरों की व्यापक सफाई की गई।

विद्युत मंत्रालय

- रघुनाथपुर कार्यालय में सूखे व गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन लगाये गए।
- CO, गुरुग्राम और RECIPMT में कर्मचारियों ने कार्यालय की सफाई करके स्वैच्छिक श्रमदान गतिविधियों में भाग लिया।
- अंडाल बाजार में कॉटन बैग वितरित किए, ताकि लोगों को 'हमारी भूमि: हमारा भविष्य' नारे के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूक किया जा सके। NHPC ने स्कूलों/आंगनबाड़ी केंद्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्थानीय लोगों के बीच एकल उपयोग पॉलीथीन बैग की रोकथाम पर आम जागरूकता चर्चा भी आयोजित की।
- टीम ने मासिक धर्म से पहले और बाद में स्वच्छता अभियान और जागरूकता शिविर तथा HIV के प्रति जागरूकता सुनिश्चित की। इंसिनरेटर स्थापित किये गए और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया।

लोक सभा चुनाव: केरल ने ग्रीन प्रोटोकॉल का पालन करने में एक मॉडल स्थापित किया केरल में 'कचरा मुक्त चुनाव' की सफलता

‘Garbage-free polls’ a success in Kerala

TRIVANDRUM: Kerala has set a model for India by implementing “green protocol” and strictly following prescribed waste disposal methods during the national election season.

The world’s largest elections began on April 19 and were staggered into seven phases. The southern state voted in the second phase on Friday.

The state’s authorities responsible for disposing of the refuse said they had “successfully achieved” the ‘garbage-free polls’ target in all 20 constituencies.

Suchitwa Mission, the state’s sanitation authority, had published procedures to be followed strictly by campaigners and election officials before electioneering commences.

Right from the start of the campaign, all stakeholders used recycled materials, and they drastically restricted single-use materials, including plastics.

Soon after the campaign concluded, the sanitation workers collected the leftover campaign materials from their source and handed them over to scientific disposal centres.

Steps have also been taken to ensure clean polling. In the state capital, Trivandrum, bio-toilets have been set up in places with more polling stations.

All polling stations in the state used electronic voting machines with a voter-verifiable paper audit trail (VVPAT), which were shifted to high-security strongrooms until the counting on June 4.

Activities have also begun establishing biodegradable and non-degradable bins and bottle booths on the Mar Ivanios College campus, where they will be kept for over a month now.

In northernmost Kasaragod, in addition to installing two types of bins in all polling booths, Suchitwa Mission assigned two of its Green Army members to supervise each booth.

An awareness campaign titled “Cast Vote by Not Defeating Nature” was organised in Malappuram. In addition, 25 centres in the district were made model polling booths.

Suchitwa Mission had published procedures to be followed strictly by campaigners and election officials before the polls commenced.
Ashraf Padanna

Nodal officers have been appointed in Palakkad to monitor the activities of HKS members on a constituency basis.

The green protocol topic was also included in the training for polling officers in the district.

In Kozhikode, Suchitwa Mission coordinated the garbage restriction activities during the campaign by deploying 4,000 green activists.

Ashraf Padanna

केरल में मतदाता शुक्रवार (26 अप्रैल) को लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान करने के लिए तैयार थे, राज्य ने चुनाव अभियानों के दौरान सभी 20 निर्वाचन क्षेत्रों में ग्रीन प्रोटोकॉल और कचरा निपटान विधियों को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सफलतापूर्वक 'कचरा मुक्त चुनाव' का लक्ष्य हासिल करके देश के लिए एक मॉडल स्थापित किया।

केरल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने सुचित्व मिशन के सहयोग से चुनाव अभियान शुरू होने से पहले अभियान चलाने वालों और चुनाव अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की।

अभियान की शुरुआत से ही, प्लास्टिक सहित एकल-उपयोग सामग्री को काफी हद तक प्रतिबंधित करने के अलावा सभी हितधारकों द्वारा पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री का उपयोग किया गया। जैसे ही अभियान समाप्त हुआ, बची हुई अभियान सामग्री को उनके स्रोत से एकत्र किया गया और हरित कर्म सेना (HKS) के सदस्यों और सफाई कर्मचारियों के सहयोग से वैज्ञानिक निपटान केंद्रों को सौंप दिया गया।

मतदान के स्वच्छ संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए। राज्य की राजधानी में उन स्थानों पर जैव शौचालय (Bio Toilets) स्थापित किए गए हैं जहां अधिक मतदान केंद्र मौजूद हैं। इसके अलावा, ‘मार इवानियोस कॉलेज’ परिसर में बायोडिग्रेडेबल और नॉन-डिग्रेडेबल कूड़ेदान और बोतल बूथ स्थापित करने के लिए कार्य शुरू किए गए, जहां EVM मशीनों को एक महीने से अधिक समय तक रखा गया था। उत्तरी कासरगोड में, सभी मतदान केंद्रों में दो प्रकार के कूड़ेदान स्थापित करने के अलावा, सुचित्व मिशन ने पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक बूथ पर दो HKS सदस्यों को नियुक्त किया। मलप्पुरम में 'प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना वोट डालें' नामक जागरूकता अभियान चलाया गया और जिले के 25 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर HKS

सदस्यों की गतिविधियों की निगरानी के लिए पलक्कड़ में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। जिले में मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में ग्रीन प्रोटोकॉल विषय को शामिल किया गया।

कोझिकोड में, अभियान के दौरान, सुचित्व मिशन ने 4,000 हरित कार्यकर्ताओं को तैनात करके NSS के साथ मिलकर कचरा प्रतिबंध गतिविधियों का समन्वय किया। ग्रीन प्रोटोकॉल के अनुसार कोझिकोड और वडकरा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रीन प्रोटोकॉल के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक और निगम/नगर पालिका सीमा में एक-एक सहित कुल 20 बूथ कार्य करेंगे।

वायनाड में, एक HKS सदस्य प्रति बूथ जिम्मेदार था, जबकि त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र में नोडल अधिकारियों को हरित चुनाव प्रशिक्षण दिया गया, इसके अलावा राजनीतिक दलों के लिए जागरूकता अभियान चलाए गए। एर्नाकुलम की गतिविधियों में ब्लॉक पंचायतों के तहत ग्रीन बूथ, वॉल पिक्चर अभियान, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग, फ्लैश मॉब, पार्टी कार्यालयों में ग्रीन बूथ, डिजिटल पोस्टर और साइकिल रैली शामिल रहीं।

अलप्पुझा में, जिला कलेक्टर ने नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को पुन: प्रयोज्य स्टील की बोतल, कपड़े का थैला और ग्रीन प्रोटोकॉल हैंडबुक वाली एक किट प्रदान की। इसके अलावा, जिले की सभी नगरपालिकाओं में दो-दो मतदान केंद्रों को ग्रीन बूथ बनाया गया।

इसी बीच, प्रवर्तन दस्ते ने चुनाव विरूपण रोधी दस्ते के समन्वय में कोट्टायम में अस्वीकृत अभियान सामग्री के उपयोग के संबंध में उल्लंघन की सूचना दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कौल ने इडुक्की में जिला प्रशासन के सहयोग से सुचित्व मिशन द्वारा आयोजित हरित निर्वाचन अभियान का शुभारंभ किया। पथनमथिट्टा में जिला प्रवर्तन दस्ते ने प्रतिबंधित फ्लेक्स के संबंध में प्रिंटिंग दुकानों का निरीक्षण किया।

कोल्लम में, जिला कलेक्टर ने हरित चुनाव के संदेश का प्रसार करने के लिए विभिन्न एथलेटिक संघों के साथ जिला साइक्लिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव 2024 के ग्रीन प्रोटोकॉल अनुपालन के संदेह और उनके उत्तर, सुचित्व मिशन और हरित केरलम मिशन के सहयोग से तैयार किए गए थे, जिन्होंने उत्पन्न होने वाले प्रदूषणकारी कचरे को कम करने के लिए चुनावों के दौरान पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करने के संबंध में हितधारकों का मार्गदर्शन किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावों वाले राज्य ने बड़े पैमाने पर 'मालिन्य मुक्तम नव केरलम' अभियान और केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (KSWM) जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के अनुरूप कार्य किया।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें: अब्राहम थॉमस रंजीत, कार्यक्रम अधिकारी सुचित्व मिशन atrmsw@gmail.com

हरियाणा में कचरे का रूपांतरण: मीना कुमारी के साथ एक गांव की यात्रा

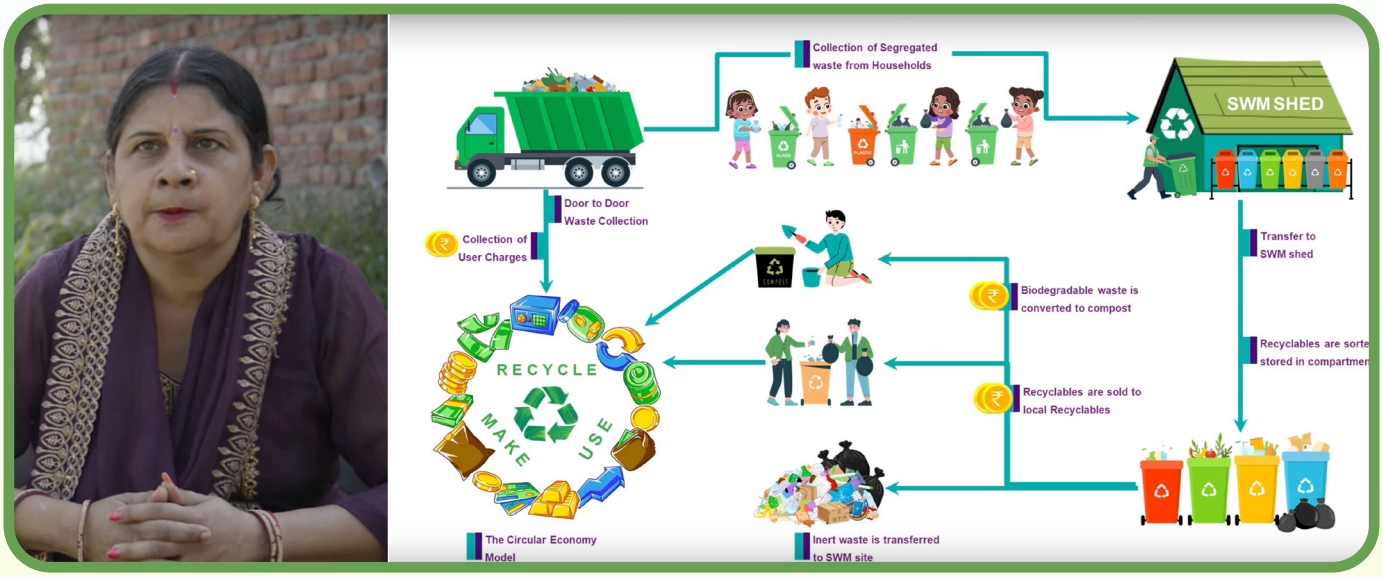

आइए कालका तहसील के मध्य में यात्रा करें, जहां हरियाणा के पंचकुला जिले के भीतर बसा मारांवाला गांव स्थित है। इस गांव में लगभग 4,000 लोग रहते हैं। मात्र संख्या से कहीं बढ़कर, इन संकरी गलियों के भीतर, परिवर्तन की एक मशाल दर्शनीय है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत एक स्वयं सहायता समूह की प्रेरणा शक्ति सुश्री मीना से मिलें, जो अटल दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं।

वर्ष 2016 में, मारांवाला गांव को एक संकट का सामना करना पड़ा। इसकी गलियां गंदी थी और वहां कोई उचित कचरा प्रबंधन प्रणाली नहीं थी। साहसी मीना ने कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने डोर-टू-डोर ठोस कचरा संग्रह का कार्य शुरू किया, एक ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर ली और एक ड्राइवर और दो कचरा संग्रहकर्ताओं की एक टीम बनाई। हर दिन, वह गांव में जाती थीं, 100-150 घरों तक पहुंचती थी और अपनी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करती थीं।
चुनौतियों के बावजूद, मीना का संकल्प और भी मजबूत हुआ। अपने SHG समूह के सहयोग से, उन्होंने 1% की ब्याज दर पर पुराना (सेकेंड हैंड) ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लिया। मीना ने बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों को अलग करने के लिए सावधानीपूर्वक अपनी टीम को कचरे को छांटने हेतु संगठित किया। कोई शेड उपलब्ध न होने के कारण, उनकी छत तरह-तरह की सामग्री के रीसाइक्लिंग केंद्र में बदल गई, जहां प्लास्टिक, स्टील, कपड़े और अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को नया सार्थक उद्देश्य मिला।

जैसे-जैसे उद्यम बढ़ता गया, वैसे-वैसे मीना की पहुंच भी बढ़ती गई। उन्होंने लगन से 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ग्लास, 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से छत की स्टील की शीट और भी बहुत कुछ सामग्री बेची। बायोडिग्रेडेबल कचरे से खाद बनाना उनके समूह के लिए आय का एक अन्य स्रोत बन गया। मीना के स्वयं सहायता समूह ने एक चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया, जिसमें उनकी अपरिहार्य सेवाओं के लिए परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से 50 रुपये वसूले गए।

प्रारंभ में, गांव ने इस परिवर्तन का विरोध किया। तथापि, मीना के दृढ़ निश्चय और सरपंच तथा अन्य नेताओं के समर्थन से, गांव के 80 प्रतिशत से अधिक लोग अब स्वेच्छा से इन आवश्यक सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। मीना जमीनी स्तर के प्रयासों की शक्ति का साक्षात प्रमाण हैं, जो यह दर्शाता है कि गांवों में कचरा प्रबंधन से कैसे बदलाव लाया जा सकता है, जिससे एक स्थायी चक्रीय अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हो।

पूरी कहानी देखने के लिए यहां क्लिक करें

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें: अभिषेक शर्मा drd@hry.nic.in

समुदायों का सशक्तिकरण: लिंगटम पदमचेन, सिक्किम में लामू डोमा भूटिया की प्रेरणादायक यात्रा

पूर्वी सिक्किम के शांत और मनोरम परिदृश्य में स्थित लिंगटम पदमचेन गांव में स्वच्छता सहयोगी या स्वच्छता चैंपियन के नाम से प्रसिद्ध लामू डोमा भूटिया के नेतृत्व में एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। उनके अथक प्रयास को ग्रामीण विकास विभाग (RDD) के सहयोग से और अधिक मजबूतीt मिली। इससे गांव सतत विकास तथा समग्र कल्याण की दिशा में अग्रसर हुआ।

इस बदलाव में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU) की स्थापना निहित है, जिसे RDD (RDD) प्रावधान द्वारा गारबेज बेलिंग कॉम्प्रेसर मशीन के माध्यम से सुविधाजनक बनाया गया है। कचरा प्रबंधन समाधानों की महती आवश्यकता को पहचानते हुए लामू डोमा भूटिया ने ग्रामिणों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी पहल को बढ़ावा दिया।

तथापि लामू डोमा भूटिया ने यह महसूस किया कि वास्तिक प्रगति का कचरा प्रबंधन से भी आगे बढ़कर विस्तार किया जाए। उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी प्रबंधन सहित व्यापक सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने की महत्ता को भी स्वीकार किया। शैक्षणिक पहलों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से उन्होंने मासिक धर्म संबंधी व्याप्त बुराइयों को दूर करने, महिला सशक्तिकरण तथा लिंगटम पदमचेन में समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

PWMU, गांव में आर्थिक स्थायित्व के प्रति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उभर कर सामने आया। लामू डोमा भूटिया के मार्गदर्शन में, यह इकाई स्व आत्मनिर्भर बना, साथ ही इसने स्थानीय लोगों विशेषत: महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर भी खोले। किचन वेस्ट को कम्पोस्ट खाद में बदलकर, समृद्ध कृषिगत प्रथाओं तथा उत्साही किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्त्रोत पैदा कर यह गांव अब अत्यंत समृद्ध हो गया है।

लामू डोमा भूटिया के नवाचारों का प्रभाव लिंगटम पदमचेन गांव से भी आगे बढ़ चुका है, जिससे पड़ोसी समुदाय भी सतत विकास के लिए इसी मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। गांव जमीना स्तर की पहलों के सशक्त परिवर्तन तथा सामुदायिक भागीदारी को प्रदर्शित करते हुए अब एक स्वच्छ, समृद्ध परिसर बन चुका है।

अपने अटल समर्पण के माध्यम से लामू डोमा भूटिया ने पर्यावरणीय संरक्षण तथा सामाजिक सशक्तिकरण की विरासत को पीछे छोड़ते हुए लिंगटम पदमचेन गांव को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनकी यात्रा लोगों द्वारा अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने और एक समय में एक पहल के प्रति प्रतिबद्धता के गहन प्रभाव की परिचायक है।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें: सुनील प्रधान, विशेष कार्य अधिकारी, osdsbmg.4@gmail.com

ईंधन संबंधी परिवर्तन: झारखंड के गुरहेट गांव में गोबर गैस परियोजना

सीतागढ़ की मनोरम पहाड़ी के पीछे स्थित गुरहेट गांव में जब आप पहुंचेंगे, तब वहां के समुदाय-चालित गोबर गैस संयंत्र वहां आपका स्वागत करते दिखेंगे। इससे 25 परिवार समृद्धि को ओर अग्रसर अग्रसर हुए हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। यह प्रयास उन स्थानीय किसानों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिन्होंने गोबर की क्षमता को पहचाना, जिसका पारंपरिक तौर पर उर्वरक तथा शक्ति उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता रहा है।

यह संयंत्र गांव में सभी परिवारों को मुफ्त गैस प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक परिवार की काफी बचत होती है। पहले, परिवारों को प्रति माह महंगे सिलेंडर खरीदने पड़ते थे, जिसकी कीमत 1,200 रूपये होती थी और जो 25 दिनों तक ही चलता था। 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस संयंत्र की स्थापना लाभार्थियों में से एक लाभार्थी द्वारा उदारतापूर्वक दान में दी गई भूमि पर की गई थी। यह कार्य ग्रामीणों, सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठन, संचालक के समर्पण से संभव हुआ, जिन्होंने समुदायों को परियोजना संबंधी समस्याओं के संबंध में पूर्ण निष्ठा से शिक्षित किया।

उजाला महिला समिति एक ऐसी अन्य संस्था है, जो समुदाय में IEC और BCC गतिविधियों संबंधी कार्य कर रही है। ये लोगों को गोबर गैस संयंत्र का उचित उपयोग, संचालन और रखरखाव संबंधी जानकारी प्रदान करती है। SBM(G) के अधिकारीगण और ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधिगण की उपस्थिति में होने वाली उनकी मासिक चर्चा के माध्यम से वे संयंत्र की कार्यशीलता और रखरखाव संबंधी बातें सीखते हैं।

एक समिति द्वारा इस गैस के उत्पादन तथा 25 परिवारों को किए जाने वाले वितरण की समीक्षा की जाती है, जिसमें आपूर्ति की सुविधा सुबह और शाम दो घंटे के लिए उपलब्ध रहती है। इस पहल के माध्यम से खाना पकाने हेतु लकड़ी, कोयला तथा LPG पर समुदाय की निर्भरता को कम हुई है। साथ ही लाभार्थियों ने गोबर गैस का उपयोग कर खाना

पकाने से होने वाली समय की बचत के महत्व को भी स्वीकार किया है।
इस योजना का क्रियान्वयन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, हजारी बाग (झारखण्ड) के द्वारा किया जा रहा है।

भविष्य की ओर देखते हुए, समुदाय का लक्ष्य अगले तीन वर्षों के भीतर 300 रुपये का मामूली उपयोगकर्ता शुल्क लागू करना है, जिससे समुदाय की भागीदारी और समर्थन के माध्यम से कार्यक्रम की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: आज़ाद हुसैन, राज्य सलाहकार- IEC एवं HRD, SBM (G) निदेशालय, झारखंड
sbmg.jhar@gmail.com या azadgarhwa@gmail.com

केरल की अभिनव छलांग: स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली से पर्यटन में बदलाव

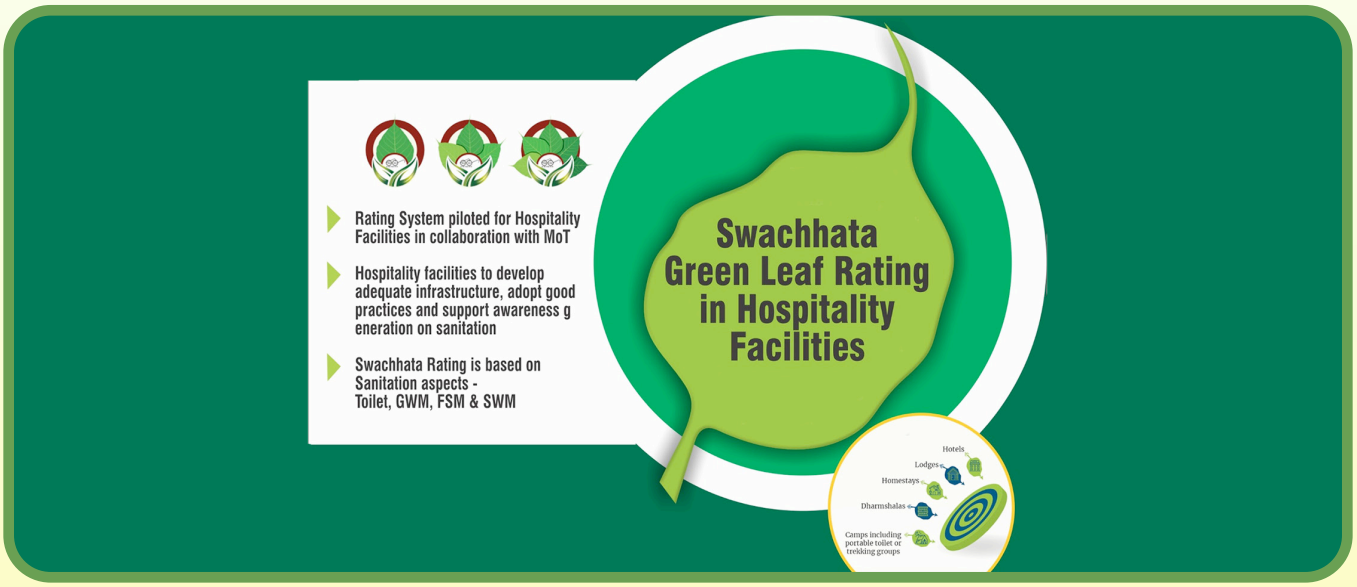

केरल, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट अभिनव दृष्टिकोणों को अपना रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से प्रारंभिक रूप से शुरू की गई स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) प्रणाली की नींव पर निर्माण करते हुए, केरल ने व्यापक रूप से अपनाने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाया है।

SGLR System, DDWS और पर्यटन मंत्रालय के बीच एक सहयोगपरक प्रयास है, जिसे स्वच्छता मानकों को बनाए रखने और जिम्मेदार पर्यटन की धारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए पहले ही शुरू किया गया था। तथापि, केरल के सक्रिय दृष्टिकोण ने इस पहल को एक कदम आगे ही बढ़ाया है, क्योंकि इसने आतिथ्य सुविधाओं के लिए स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु एक उपयोगकर्ता-अनुकूल (User Friendly) संबंधी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म प्रस्तुत किया है।

नई शुरू की गई ऑनलाइन प्रणाली के साथ, आतिथ्य सुविधाएँ अब पंजीकरण कर सकती हैं और अपना खाता बना सकती हैं, जिससे स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया सरल हो जाती है। विशिष्ट क्रेडेंशियल का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, उपयोगकर्ताओं को एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड पर पुनः निर्देशित किया जाता है। यहाँ, वे निर्दिष्ट बटन 'मूल्यांकन रेटिंग प्राप्त करें' पर क्लिक करके आसानी से मूल्यांकन रेटिंग खंड तक पहुँच सकते हैं।

रेटिंग पेज उपयोगकर्ताओं को DDWS द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन रैंकिंग प्रारूप के अनुसार अपने स्कोर को चिह्नित करने की अनुमति देता है। 'हां' या 'नहीं' विकल्पों के सावधानीपूर्वक चयन के माध्यम से, ये सुविधाएं स्वच्छता संबंधी मानकों के साथ अपने अनुपालन का सटीक रूप से आकलन कर सकती हैं। एक बार SGLR की तीन मुख्य श्रेणियों के तहत प्रविष्टियां पूरी हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता सबमिट बटन पर एक साधारण क्लिक के साथ सीधे पोर्टल के माध्यम से अपना स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह अभिनव प्रणाली लॉगिन के तीन स्तरों - राज्य स्तर, जिला स्तर और उपयोगकर्ता स्तर को प्रस्तुत करती है जो एक व्यापक और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। सुविधाएं उनके आवेदन जमा कर सकती हैं, जिन्हें फिर जिला-स्तरीय सत्यापन समितियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। सत्यापन टीम द्वारा प्रदान किए गए अंकों को सुविधाओं की रैंकिंग के लिए माना जाता है, जिससे निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।
इसके अलावा, यह प्रणाली सार्वजनिक उपयोगकर्ता पंजीकरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे आतिथ्य सुविधाओं को स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार मिलता है। स्व-पंजीकरण के माध्यम से, उपयोगकर्ता अपना खाता बना सकते हैं और अपनी मूल्यांकन यात्रा का स्वामित्व ले सकते हैं, जिससे जवाबदेही और निरंतर सुधार की संस्कृति में योगदान मिलता है।

इस उपयोगकर्ता-अनुकूल (User Friendly) संबंधी ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के लिए केरल का सक्रिय दृष्टिकोण जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और आतिथ्य क्षेत्र में स्वच्छता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, केरल का लक्ष्य SGLR System को व्यापक रूप से अपनाना और अपने पर्यटन उद्योग के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है।

निष्कर्ष के तौर पर, ऑनलाइन स्व-पंजीकरण और मूल्यांकन मंच शुरू करने में केरल की अभिनव छलांग जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समवेत प्रयासों और सक्रिय पहलों के माध्यम से, केरल आतिथ्य क्षेत्र में स्वच्छता मानकों के लिए नए मानक स्थापित करते हुए, उदाहरण के तौर पर अग्रणी बना हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए: अब्राहम थॉमस रेन्जिथ, कार्यक्रम अधिकारी सुचित्वा मिशन atrmsw@gmail.com

सुरक्षा और गरिमा संवर्धन: रायपुर में स्वच्छाग्रही प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने यूनिसेफ के सहयोग से 9-10 मई 2024 को रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षकों के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (ToT) का आयोजन किया। यह प्रशिक्षण रायपुर में स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) में नियोजित सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा पर केंद्रित था। स्वच्छाग्रही के रूप में जाने जाने वाले ये सफाई कर्मचारी ज्यादातर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्य हैं।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एक लाख से अधिक महिला स्वच्छाग्रहियों को उनकी सुरक्षा और गरिमा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करने के महत्व और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में सभी 33 जिलों को कवर करने वाले 55 जिला और ब्लॉक समन्वयकों, जिला सलाहकारों और ब्लॉक समन्वयकों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों ने स्वच्छता कर्मचारियों के सामने प्रतिदिन आने वाली विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों के बारे में सीखा तथा स्वच्छाग्रहियों की कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार कीं।

SBM-G, छत्तीसगढ़ के मिशन निदेशक सुश्री चंदन संजय त्रिपाठी ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। उन्होंने SBM-G के तहत सभी स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया और प्रतिभागियों से सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य जांच तथा अन्य स्वास्थ्य लाभों की पहुंच सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने एक क्षेत्र के दौरे का वर्णन किया जहां स्वच्छाग्रही ठोस कचरा पृथक्करण में कार्यरत थी। उसे अपने कार्य के पश्चात स्नान करने के बावजूद लगातार खुजली महसूस हो रही थी। इस वर्णन ने प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता के महत्व को दर्शाया।

छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के फील्ड ऑफिस के प्रमुख जॉब जकारिया ने स्वच्छता कर्मचारियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ कर उनके काम के माहौल और आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर उनके जीवन में सुधार लाने के महत्व पर जोर दिया।

प्रशिक्षण सत्रों में यूनिसेफ के भागीदार समर्थन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, यूनिसेफ की WASH-CCES टीम और SBM-G के राज्य सलाहकारों के विशेषज्ञों ने स्वच्छता कर्मचारियों के समग्र कल्याण तथा पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई विषयों को शामिल किया।

अधिक जानकारी के लिए, sbmg.cg@gov.in पर SBM (G), छत्तीसगढ़ या rupeshrathore2000in@gmail.com पर SBM (G) राज्य समन्वयक रूपेश राठौर से संपर्क करें।

राज्य से समाचार: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

शिव सिंह मीणा
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण

एक अग्रणी कदम में, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 10 जनवरी, 2019 तक सभी सड़क निर्माण परियोजनाओं में 8-10% प्लास्टिक कचरे के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। इस प्रगतिशील नीति ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रकटित किया। सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे को एकीकृत करके, हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास की दोहरी चुनौतियों का समाधान किया।

पिछले कुछ वर्षों में, हमने इस प्रयास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमारी विधि में बिटुमिनस मिक्स में एक योजक के रूप में 8-10% कटा हुआ प्लास्टिक कचरे का उपयोग करना शामिल है, जो हमारी सड़कों के स्थायित्व और दीर्घायु को बढ़ाता है। 2021 से 2024 तक के आंकड़े हमारी प्रगति को दर्शाते हैं: 2021-22 में, हमने 18.76 किमी सड़कों के निर्माण के लिए 14,146 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया। यह 2022-23 में 24.64 किमी के लिए बढ़कर 16,087 किलोग्राम और 2023-24 में 131.99 किमी के लिए उल्लेखनीय 17,070 किलोग्राम हो गया। यह पर्याप्त वृद्धि, विशेष रूप से 2023-24 में सड़क की लंबाई में, संचालनों में हमारे महत्वपूर्ण पैमाने को प्रदर्शित करती है।

सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग कई लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से यह हमारे भौगोलिक और पर्यावरणीय संदर्भ के अनुकूल है। प्लास्टिक एडिटिव्स से निर्मित सड़कें टूट-फूट के प्रति अधिक प्रतिरोधी हैं, जो पानी से होने वाले नुकसान के प्रति बेहतर प्रतिरोध प्रदर्शित करती हैं, जो हमारे यहां भारी मानसून की बारिश को देखते हुए महत्वपूर्ण है। यह पहल न केवल हमारे प्लास्टिक कचरे को प्रबंधित करने में मदद करती है, बल्कि एक पर्यावरण प्रदूषक को एक मूल्यवान संसाधन में बदल देती है, कचरे की मात्रा को भी कम करती है जो अन्यथा लैंडफिल या समुद्र में निपटाया जाएगा। इसके अलावा, सड़क निर्माण में प्लास्टिक को शामिल करने से समग्र लागत कम हो सकती है। प्लास्टिक-बिटुमेन मिश्रण को समय के साथ कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिससे मरम्मत और पुनरुत्थान संबंधी बचत होती है। प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण करके, हम सड़क निर्माण से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान करते हैं।

हालांकि हमारी प्रगति सराहनीय रही है, लेकिन हम कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण और प्रसंस्करण के लिए व्यवस्थित प्रयासों तथा मजबूत अवसरंचना की आवश्यकता होती है। अलग-अलग जलवायु और भार स्थितियों के लिए प्लास्टिक-बिटुमन मिश्रण को अनुकूलित करने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास आवश्यक है। भविष्य में, हम शून्य अपशिष्ट द्वीप समूह की स्थिति हासिल करने की दिशा में इस पहल का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्लास्टिक कचरा संग्रह बढ़ाने की योजना चल रही है। हम प्लास्टिक सड़क निर्माण के तकनीकी पहलुओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग की भी संभावना तलाश रहे हैं।

सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की हमारी पहल पर्यावरण और बुनियादी ढांचे की चुनौतियों को दूर करने में नवीन सोच का एक वसीयतनामा है। प्लास्टिक कचरे को संसाधन में बदलकर हम सतत विकास के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण न केवल मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान देता है बल्कि व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ भी संरेखित करता है, जिससे यह अन्य क्षेत्रों में अनुकरण करने लायक मॉडल बन जाता है। चूंकि हम इन व्यवहारों को विकसित और परिष्कृत करना जारी रखते हैं, अत: समुदाय का समर्थन और भागीदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। साथ मिलकर, हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक स्वच्छ, हरित और अधिक निश्चित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तमिलनाडु का अभिनव दृष्टिकोण

परिचय

प्लास्टिक प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन गया है, लेकिन तमिलनाडु का प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अपना सक्रिय और अभिनव दृष्टिकोण है। यह लेख राज्य भर में विभिन्न पंचायतों के परिवर्तनकारी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय संचालित पहलों के माध्यम से प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

अग्रणी पहल

2020 में, मयिलादुथुराई जिले में मुदिकंदनल्लूर पंचायत ने जिला-स्तरीय प्लास्टिक श्रेडिंग यूनिट की स्थापना करके एक अभूतपूर्व पहल का नेतृत्व किया। मशीनरी और बुनियादी ढांचे में 9,79,900 रुपये के निवेश के साथ, स्थानीय स्वच्छता कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों ने एक वर्ष के भीतर 34,969 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे को एकत्र किया तथा छोटे टुकडों में काटा, जिससे राजस्व में 12,87,926 रुपये का संवर्धन हुआ। इस प्रयास ने न केवल प्रारंभिक निवेश की प्रतिपूर्ति की बल्कि स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित किया।

SBM-G चरण II के तहत, तमिलनाडु ने प्रति ब्लॉक 16 लाख रुपये के वित्तपोषण के साथ व्यापक PWM समाधानों को अपनाया है। मुदिकंदनल्लूर की सफलता से प्रेरित होकर, राज्य ने इसी तरह की पहल को जोर देते हुए आगे बढ़ाया है।

तमिलनाडु की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तमिलनाडु का संरचित दृष्टिकोण स्रोत पर कचरे को अलग करने वाले परिवारों के साथ शुरू होता है। समर्पित थूईमाई कावलर विशेष रूप से नामित वाहनों का उपयोग करके इस कचरे को डोर-टू-डोर इकट्ठा करते हैं। एकत्र किए गए कचरे को फिर पंचायतों द्वारा बनाए गए पृथक्करण और भंडारण शेड में ले जाया जाता है, जहां द्वितीयक पृथक्करण प्लास्टिक कचरे को अन्य सामग्रियों से अलग करता है।

ब्लॉक स्तर पर, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ (PWMUs) एकत्रित कचरे को मूल्यवान संसाधनों में संसाधित और पुनर्चक्रित करती हैं। स्थानीय कबाड़ी वालों के साथ साझेदारी के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, जबकि गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सड़क निर्माण में उपयोग के लिए धूल हटाने और कतरन सहित आगे की प्रक्रिया से गुजरता है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के घटक

तमिलनाडु की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों के लिए केंद्रीय प्लास्टिक श्रेडर है, जो 100-125 किलोग्राम/घंटा संसाधित करने में सक्षम है। वैकल्पिक धूल हटाने वाले यंत्र कटे हुए प्लास्टिक की शुद्धता को बढ़ाते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले अंत उत्पादों को सुनिश्चित करते हैं। सीमेंट उद्योग लिंकेज वाले कुछ PWMU भी कचरे को कॉम्पैक्ट करने के लिए बेलिंग मशीनों का उपयोग करते हैं, और प्राप्त तथा कटे हुए प्लास्टिक को मापने के लिए वजन मशीनों का उपयोग करते हैं।

संचालन और रखरखाव

स्वयं सहायता समूह (SHG) और पंचायतें PWM के रखरखाव, सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने और स्थानीय जुड़ाव तथा रोजगार के अवसरों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं

पर्यावरणीय स्थिरता के लिए तमिलनाडु की प्रतिबद्धता इसकी उपलब्धियों में परिलक्षित होती है। क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर, राज्य ने 388 प्रस्तावित इकाइयों में से 315 कार्यशील PWM स्थापित किए हैं। माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने 2023-24 में कटे हुआ प्लास्टिक का उपयोग करके 1,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना की घोषणा की, जो पिछले वर्षों में 730 मीट्रिक टन कटे हुआ प्लास्टिक का उपयोग करके बनाई गई लगभग 1,623 किलोमीटर सड़कों की सफलता पर आधारित है।

आर्थिक व्यवहार्यता और संविदाकार अनुपालन

सड़क निर्माण के लिए कटे हुए प्लास्टिक के वित्तपोषण के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता इसकी सफलता सुनिश्चित करती है। IRC कोड IRC SP 98:2013 बिटुमेन प्रतिस्थापन के रूप में सड़क निर्माण में 8% प्लास्टिक के उपयोग की अनुमति देता है। बिटुमेन की कीमत 45 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है, जबकि कटा हुआ प्लास्टिक 35 रुपये प्रति किलोग्राम मिल जाता है। यह आर्थिक प्रोत्साहन, अनिवार्य संविदाकर अनुपालन के साथ, सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे को व्यापक रूप से अपनाना सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

PWM के लिए तमिलनाडु का दृष्टिकोण नवाचार, सामुदायिक जुड़ाव और स्थिरता का उदाहरण है। कार्यनीतिक साझेदारी, कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों और समुदाय संचालित पहलों के माध्यम से, राज्य अपशिष्ट प्रबंधन में एक अग्रणी के रूप में उभरा है। उनकी यात्रा देश भर में प्रभावी पर्यावरण नीतियों और व्यवहारों को आकार देने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिससे हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: सहायक निदेशक (एसबीएम), ग्रामीण विकास और पंचायत राज निदेशालय tnsbmg@gmail.com

विश्व पृथ्वी दिवस समारोह

22 अप्रैल, 2024 को, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा समर्थित HDFC बैंक और सेन्टर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत में 17 स्थानों पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

- इस पहल के अंतर्गत छह सफाई अभियानों और अभियानों के माध्यम से 5,413 किलोग्राम सूखे और प्लास्टिक कचरे का संग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त, 9 सामग्री संग्रहण सुविधा केंद्रों (MRF) में 33.11 मीट्रिक टन सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया।
- सामुदायिक भागीदारी: 1,900 से अधिक हितधारकों और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया, 100 पौधे लगाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से कचरे में कमी और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया।
- हाथ धोने के अभिनव समाधान: स्वच्छता और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 900 से अधिक SATO नल वितरित किए गए। परियोजना का लक्ष्य जून 2024 तक 1,00,000 नल वितरित करना है।
- शैक्षणिक प्रयास: जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और कचरे को कम करने, पुन: उपयोग करने और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों के बारे में समुदायों को शिक्षित करने के लिए सोलह जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- विश्व पृथ्वी दिवस के बाद लामबंदी संबंधी गतिविधि के अंतर्गत, अन्य 7 दिनों (23-29 अप्रैल, 2024) की अवधि में 9 परियोजनागत स्थलों ने 276.37 मीट्रिक टन सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया (जिसमें से 55% प्लास्टिक है)। इसमें से 8.197 मीट्रिक टन गीला कचरा भुवनेश्वर में एकत्रित किया गया है।

चित्र में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कई शब्द छिपे हैं। इनमें कम-से-कम 5 शब्द ढूंढिए। आपकी सुविधा के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है।

W	C	L	E	A	N	T	W	B	P	Z
O	A	B	C	I	D	K	M	L	N	B
D	G	K	A	T	E	W	T	A	G	M
K	E	T	N	O	F	A	E	C	E	S
I	H	Y	G	I	E	N	E	K	R	A
L	A	D	O	L	C	E	S	W	M	N
I	N	U	D	E	A	W	D	A	B	I
C	D	N	B	T	T	O	U	T	A	T
N	W	G	T	L	I	E	S	E	I	A
W	A	T	E	R	O	S	T	R	E	T
E	S	R	N	Y	A	F	I	D	P	I
I	H	R	N	Y	A	F	I	D	P	O
R	E	C	Y	C	L	E	N	R	T	N

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले swachhbharat@gov.in पर अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in